



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022020-216426
CG-DL-E-27022020-216426

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 775]
No. 775]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 25, 2020/फाल्गुन 6, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2020/PHALGUNA 6, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2020

का.आ. 848(अ).— जबकि, सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण के लिए पहचान पत्र दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग, सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता तथा दक्षता लाता है, और लाभार्थियों को सुविधाजनक और सहज तरीके से सीधे अपना हक प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और आधार किसी की पहचान साबित करने के लिए कई प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और जबकि, भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (इसके पश्चात इसे विभाग कहा जाएगा) द्वारा, भारतीय फुटबियर, चमड़ा और सहायक वस्तु विकास कार्यक्रम (आईएफएलएडीपी) की मानव संसाधन विकास उप-योजना के अंतर्गत प्राथमिक कौशल विकास कार्यक्रम नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (इसके पश्चात इसे योजना कहा जाएगा) को प्रशासित किया जा रहा है। इस योजना को विभाग द्वारा इसके लिए चयनित विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे फुटबियर डिजाइन और विकास संस्थान (एफडीडीआई), केंद्रीय फुटबियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई) तथा इसी प्रकार के अन्य संस्थानों (इसके पश्चात इन्हें कार्यान्वयन एजेंसियां कहा जाएगा) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;

और जबकि, योजना के तहत, योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, प्राथमिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो और जो शॉप-फ्लोर कार्यों में प्रवेश स्तर पर

इस क्षेत्र में पहले से कार्यरत न हों और इसमें महिलाओं अथवा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अल्पसंख्यक अथवा कमजोर वर्गों और गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों (इसके पश्चात इसे लाभार्थी कहा जाएगा) को प्राथमिकता दी जाएगी;

और जबकि, प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात प्रति लाभार्थी अधिकतम 15,000/- रुपए (सब कुछ शामिल) की दर से भारत सरकार की सहायता में से वजीफे के रूप में प्रति लाभार्थी 1,500/- रुपए (इसके पश्चात इसे वित्तीय लाभ कहा जाएगा) की राशि प्रदान की जाती है, जिसमें भारत के संचित कोष से किया गया आवर्ती व्यय शामिल है;

इसलिए अब, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवा का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (इसके पश्चात इसे उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 7 के प्रावधानों अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, नामतः -

1. (1) योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को, आधार नंबर का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा।

(2) इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को, जिसके पास आधार नंबर नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, उसे इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षु के तौर पर पंजीकरण करने से पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति को आधार हेतु नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (यूनीक आइडेंटिफिकेशन एथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) पर जाना होगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के जरिए विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे लाभार्थियों को, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, आधार नामांकन सुविधा प्रदान करे और ऐसे मामले में जहां संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के साथ समन्वय करते हुए या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार पंजीकरण सुविधा प्रदान करेगा:

बशर्ते कि जब तक व्यक्ति को आधार नहीं सौंपा जाता, तब तक ऐसे व्यक्ति को इस योजना के लाभ दिए जाएंगे, जो निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन होंगे :-

- (क) यदि उसने आधार के लिए नामांकन किया है, तो उसके आधार की नामांकन पहचान पर्ची; और
- (ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात्:-
 - (i) फोटो सहित बैंक अथवा डाकघर की पासबुक; अथवा
 - (ii) भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; अथवा
 - (iii) राशन कार्ड; अथवा
 - (iv) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; अथवा
 - (v) किसान फोटो पासबुक; अथवा
 - (vi) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा जारी किया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस; अथवा
 - (vii) ऐसे व्यक्ति का राजपत्रित अधिकारी द्वारा आधिकारिक लेटरहेड पर फोटो सहित जारी किया गया प्रमाण पत्र; अथवा
 - (viii) पासपोर्ट; अथवा
 - (ix) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज

बशर्ते कि उपर्युक्त दस्तावेजों की किसी ऐसे अधिकारी द्वारा यह जांच की जाए जो विभाग द्वारा नमोदित किया गया हो।

2. इस योजना के तहत लाभार्थियों को सुविधाजनक ढंग से लाभ प्रदान करने के लिए, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने हेतु कि लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत आधार की आवश्यकता से अवगत कराने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा।

3. उन सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण अथवा किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, तो निम्नलिखित अपवाद संबंधी सुधारात्मक तंत्रों को अपनाया जाएगा, अर्थात:-

- (क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आइरिश स्कैन अथवा चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा को अपनाया जाएगा, जिसके लिए विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से आइरिश स्कैनर का प्रावधान करेगा अथवा निर्बाध तरीके से लाभ पहुंचाने हेतु फिंगर प्रिंट प्रमाणीकरण के साथ-साथ चेहरे का प्रमाणीकरण भी करेगा;
- (ख) यदि उंगलियों के निशान अथवा आइरिश स्कैन अथवा चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में, जहां भी व्यवहार्य और स्वीकार्य हो, आधार वन टाइम पासवर्ड अथवा सीमित समय वैधता वाले समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड, जैसा भी मामला हो, से प्रमाणीकरण किया जाएगा;
- (ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक अथवा आधार वन टाइम पासवर्ड अथवा टाइम-आधारित वन-टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, ऐसे मामलों में योजना के लाभ मूल आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते हैं जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रेस्पॉन्स कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है तथा क्विक रेस्पॉन्स कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से उचित स्थानों पर प्रदान की जाएगी।

4. योजना के अंतर्गत कोई भी प्रामाणिक लाभार्थी अपने लाभ प्राप्त करने से वंचित न रह जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभांतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के दिनांक 19 दिसंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी में यथाविनिर्दिष्ट अपवाद वाले मामलों से निपटने के तंत्र का अनुपालन करेगा।

5. यह अधिसूचना असम और मेघालय राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 5/16/2016-चमड़ा]

अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2020

S.O. 848(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (*hereinafter referred to as the Department*) in Ministry of Commerce and Industry of Government of India is administering a central sector scheme, namely, the **Primary Skill Development Programme under Human Resource Development sub-scheme of Indian Footwear, Leather and Accessories Development Programme (IFLADP)** (*hereinafter referred to as the Scheme*). The Scheme is implemented by the Department through various Implementing Agencies selected for this purpose like Footwear Design and Development Institute (FDDI), Central Footwear Training Institute (CFTI) and other Institutes of similar standing (*hereinafter referred to as the Implementing Agencies*);

And whereas, under the Scheme primary skill development training programmes are organised for the persons who have attained the minimum age of eighteen years and are not already employed in the sector at entry level in shop-floor operations, and preferably who are women or from the Scheduled Caste or Scheduled

Tribe or minority or weaker sections and below the poverty line (*hereinafter referred to as the beneficiaries*), as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the Scheme provides an amount of Rs.1,500/- as stipend per beneficiary (*hereinafter referred to as the benefit*) after completion of the training out of the Government of India's assistance @ maximum of Rs. 15,000/- per beneficiary (all inclusive), which involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual desirous of availing the benefit under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment before registering as trainee under the Scheme, provided he is entitled to obtain Aadhaar as per provisions of section 3 of the said Act, and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in for Aadhaar enrolment.
- (3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefit under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:-

- (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; and
- (b) any one of the following documents, namely:
 - (i) Bank or Post office Passbook with Photo; or
 - (ii) Voter Identity Card issued by the Election Commission of India; or
 - (iii) Ration Card; or
 - (iv) Permanent Account Number (PAN) Card issued by Income Tax Department; or
 - (v) Kisan Photo passbook; or
 - (vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
 - (vii) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer on the official letter head; or
 - (viii) Passport; or
 - (ix) any other document as specified by the Department:

Provided further that the aforesaid documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries conveniently under the Scheme, the Department through its Implementing Agencies shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following exception handling mechanisms shall be adopted, namely:-

- (a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agencies shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
- (b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
- (c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar

letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agencies.

4. In order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum No. D-26011/04/2017-DBT dated the 19th December, 2017 of Direct Beneficiary Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory administrations, except the States of Assam and Meghalaya.

[F.No. 5/16/2016-Leather]

ANIL AGRAWAL, Jt. Secy.